राजनीतिक तिलिस्मों पर फतह का महायज्ञ

जनसंपर्क बादशाह

www.picmp.com

आरएनआई निबंधन संख्या-एमपीएचआईएन1999।4107

डाक पंजीयन-मप्र।भोपाल।371।18-20

वर्ष-21,अंक-28(पच्चीस सालों से प्रकाशित) भोपाल,28जुलाई,मंगलवार 2020 पेज-8,मूल्य पांच

शिवराज दहाड़ेः अपराधियों में खौफ जरूरी

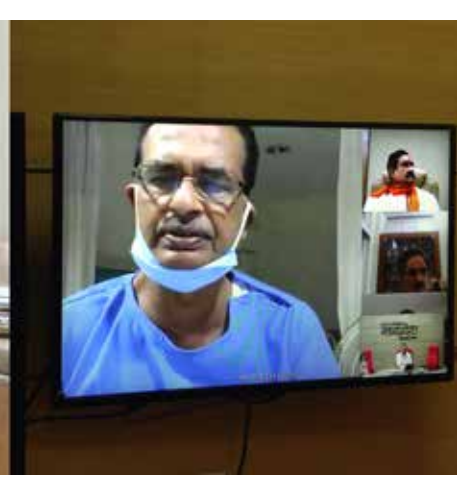

भोपाल,27 जुलाई (प्रेस सूचना केन्द्र)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अपराधियों में खौफ होना जरूरी है। उनसे सख्ती से निपटा जाये, किसी प्रकार की रियायत नहीं बरती जाये। प्रदेश में अपराधी तत्वों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान को निरंतर जारी रखें। इस अभियान को प्रशासन और पुलिस संयुक्त रूप से गति दें। मुख्यमंत्री श्री चौहान अस्पताल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून-व्यवस्था एवं कोरोना नियंत्रण की व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव मो. सुलेमान भी अपने-अपने कार्यालय से शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिये जरूरी है कि इसे जन-आंदोलन का रूप दिया जाये। इसमें शासन-प्रशासन के साथ ही सभी आमजन, समाज और स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाये। साथ ही नागरिकों को जागरूक करने के लिये विभिन्न समुदायों के संत और समाज के प्रमुख लोगों से अपील करवायें। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग आवश्यक है। लोग इसे अपनायें और जो लोग गाइड-लाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्ती से पेश आयें। उन्होंने कहा कि कोरोना की टेस्टिंग की संख्या भी बढ़ाई जाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि रिकवरी की दिशा में बढ़ते कदम की आशा को तोड़ना नहीं है, विश्वास में बदलना है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सागर, दमोह और टीकमगढ़ में कोरोना मरीजों के उपचार के लिये किये गये प्रबंधों की समीक्षा की। उन्होंने सागर मेडिकल कॉलेज में उपचार संबंधी व्यवस्थाओं पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि व्यवस्थाएँ बेहतर नहीं हो पा रही हैं। गृह मंत्री डॉ. मिश्रा द्वारा मेडिकल कॉलेज के पूर्व डीन को ही पुनः व्यवस्थाएँ सौंपे जाने का प्रस्ताव रखा गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सहमति व्यक्त करते हुए निर्णय लेने के निर्देश चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग को दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सभी जेलों में ध्यान देने की जरूरत है। कैदी की रिहाई के पहले उसकी टेस्टिंग अवश्य करें, उसके बाद ही उसे घर भेजें। गृह एवं जेल मंत्री डॉ. मिश्रा ने बताया कि कैदियों को कोरोना टेस्टिंग के बाद ही जेल में रखा जा रहा है। जेल विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में संयुक्त निर्देश जारी कर दिये हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लोगों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण-काल में कूलर और ए.सी. का प्रयोग न करें। इसे अपनाने से बचें। कोविड नियंत्रण के लिये हमें अपने और अपने परिवार के लिये यह सुरक्षित उपाय अपनाने होंगे। उन्होंने खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि मैं जहाँ उपचार ले रहा हूँ, वहाँ कूलर और ए.सी. का उपयोग नहीं किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कानून-व्यवस्था की समीक्षा में विगत एक सप्ताह में गृह विभाग द्वारा की गई कार्यवाही पर संतोष जताते हुए बेहतर कार्य के लिये विभाग और अधिकारियों को बधाई दी। बैठक में बताया गया कि गत सप्ताह में 332 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। आगर-मालवा में एक हजार बीघा शासकीय जमीन अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराई गई। पुलिस द्वारा 27 चिटफण्ड कम्पनियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किये गये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि चिटफण्ड कम्पनियों से गरीबों को पैसा भी वापस दिलवाना सुनिश्चित किया जाये। इसके लिये अभियान लगातार जारी रखें। श्री चौहान ने कहा कि कानून-व्यवस्था को बनाये रखते हुए यह भी ध्यान रखें कि नौजवान पीढ़ी नशे की गिरफ्त में न फँसे। गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि चिटफण्ड कम्पनियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जा रही है और ऐसा पहली बार हो रहा है कि चिटफण्ड कम्पनियों से पैसा वापस दिलवाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने आय बढ़ाने के लिए बनाई समिति

नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कार्यभार संभालते ही विभाग की लंबित पड़ी उन योजनाओं पर काम शुरू कर दिया है जिनसे आर्थिक संकट से जूझते नगरीय निकायों की दशा संभाली जा सके।

भोपाल 27 जुलाई(प्रेस सूचना केन्द्र)। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि नगरीय निकायों की आय ब ?ाने के सुझाव देने के लिये आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास की अध्यक्षता में समिति गठित करें। समिति में भोपाल और इंदौर नगर निगम के कमिश्नर सहित अन्य सदस्य होंगे। श्री सिंह ने 15 दिन में सुझाव संबंधी रिपोर्ट देने के निर्देश दिये। उन्होंने नगरीय निकायों के मास्टर प्लान में सुधार करने के संबंध में विचार के लिये नगर एवं ग्राम निवेश के अधिकारियों की एक समिति बनाने के निर्देश भी दिये। श्री सिंह ने कहा कि यह समिति नगरीय क्षेत्रों में आने वाली कृषि भूमि सहित अन्य विषयों पर विचार कर रिपोर्ट देगी।

श्री सिंह ने कहा कि पथ-विक्रेताओं को लोन देने के संबंध में नगरीय निकायों द्वारा किये जा रहे कार्यों की प्रति सप्ताह ग्रेडिंग करें। लगातार पीछे रहने वाले नगरीय निकायों के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करें।

एक से 15 अगस्त तक चलेगा मास्क लगाने के लिये जागरूकता अभियान

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि एक अगस्त से 15 अगस्त तक सभी नगरीय निकायों में नागरिकों को मास्क लगाने के लिये प्रेरित करने के लिये जागरूकता अभियान चलायें। अभियान में स्वयंसेवी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाये। श्री सिंह ने कहा कि शहर के प्रमुख चौराहों पर स्टाल लगाकर वालेंटियर्स की मदद से मास्क नहीं लगाने वालों को रोककर समझाइश दें।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने कहा कि नवगठित 30 नगरीय निकायों में भी विकास कार्य प्रारंभ किये जायें। उन्होंने अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण की कार्यवाही समय-सीमा में करने के निर्देश दिये। श्री सिंह ने कहा कि सीवरेज सिस्टम के सभी कार्यों की मॉनीटरिंग कर इन्हें समय-सीमा में पूरा कराएँ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में रुके हुए कार्य शुरू कराए जाएं। श्री सिंह ने कहा कि स्मार्ट सिटी के कार्यों की सतत समीक्षा की जरूरत है।बैठक में प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री नीतेश व्यास और आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव उपस्थित थे।

राजनीतिक तिलिस्मों पर फतह का महायज्ञ
जासूस बादशाह
भोपाल,28जुलाई,मंगलवार 2020

कोरोना संकट को बनाएं विकास की कुंजी

पूरी दुनिया में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। लगभग साढ़े छह लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। डेढ़ करोड़ से ज्यादा लोग इस रहस्यमयी बीमारी की चपेट में हैं। भय और निराशा का वातावरण बन रहा है। अब तक कोरोना के इलाज के लिए कोई विश्वसनीय वैक्सीन नहीं बन सकी है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बीमारी के इलाज का टीका खोज रहे हैं। लगभग 130 कंपनियां वैक्सीन बनाने में जुटी हैं।इससे पहले इतनी तेज गति का अनुसंधान किसी बीमारी को लेकर नहीं किया गया। दस सालों में बनने वाली वैक्सीन को चंद महीनों में तैयार करने के लिए वैज्ञानिकों ने सुपर कंप्यटरों की मदद ली है।ये आधुनिक कंप्यूटर कई लाख गणनाएं निपटाकर वैक्सीन का असर जांच रहे हैं। इसके बावजूद प्रकृति का कोई विकल्प नहीं है।वे गणनाएं जुगाड़ की वैक्सीन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहीं हैं लेकिन इन तात्कालिक वैक्सीनों का असर तो कई सालों बाद ही सामने आ पाएगा। आयुर्वेदिक दवाओं ने कोरोना वायरस से निपटने में काफी सहारा दिया है इसके बावजूद जब तक इन दवाओं का वैज्ञानिक आधार नहीं तलाश लिया जाएगा तब तक विश्व को इनकी उपयोगिता समझ में नहीं आएगी। कोरोना से निपटने में जैसे हमारी देशी दवाईयां कारगर साबित हो रहीं हैं उसी तरह अर्थव्यवस्था के संकट से भी निजात दिलाने में हमारी देशी अर्थनीति कारगर साबित हो सकती है। कर्ज आधारित आयातित अर्थव्यवस्था का जंजाल हम भुगत रहे हैं। वैश्विक संस्थाओं से कर्ज लेने की होड़ जगाकर कांग्रेसी सरकारों ने बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया था उससे देश कर्ज के दलदल में फंस गया है। आज भारत पर 90 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज है। नोटबंदी के बाद जब अर्थव्यवस्था को रीसेट किया गया तो काली कमाई का बड़ा हिस्सा समाप्त हो गया और घोषित मुद्रा में इजाफा हुआ। यही वजह थी कि तब देश को मालूम पड़ा कि उस पर कर्ज कितनी तेजी से बढ़ता जा रहा है। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में कर्ज को घटाने के लिए उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया। फिजूलखर्ची पर रोक लगाकर राज्यों को प्रेरित किया कि वे पूंजी उत्पादन के अपने ढांचे को सुधारें। इसका नतीजा ये हुआ कि देश में पूंजी का डिजिटलाईजेशन तेजी से हुआ है। देश में समानांतर कारोबार करना कठिन हुआ है। इस बीच कोरोना ने सुधारों की इस रफ्तार का भट्टा बिठा दिया। लॉक डाउन से जूझते शहरों की आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ गईं हैं।ऐसे में भारत के गांवों ने देश को सहारा दिया है। मोदी सरकार ने गांवों में आर्थिक सुधारों की नींव रखते हुए खाद्य उत्पादक संगठन (एफपीओ) बनाने पर जोर दिया है। लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि वे गांव स्तर पर खुद के ऐसे संगठन बनाएं जो किसानों की आय दोगुनी करने में सहयोगी साबित हों। इससे न केवल फसलों का उत्पादन बढ़े बल्कि ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर भी बढ़ें। मनरेगा के माध्यम से कांग्रेस की सरकारों ने जो फर्जी रोजगार मुहैया कराने की योजना लागू की थी वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है।उससे इकानामी तो बढ़ी नहीं बल्कि देश पर कर्ज का बोझ बढ़ता चला गया है। जिन राज्यों की सरकारों ने देश के आर्थिक सुधारों के साथ कदमताल किया है उन राज्यों में विकास का पहिया तेज गति से घूमा है लेकिन जो राज्य राजनैतिक रंजिशों के चलते पुरानी नीतियों से चिपटे पड़े हैं वे आज भी करवट नहीं ले पा रहे हैं। हमारे किसानों पर बड़ी जवाबदारी है। उन्हें आढ़तियों के चंगुल से छुड़ाने के लिए सरकार ने ई मंडी और उपज को दुनिया भर में बेचने की छूट दी है। जाहिर है कि भारत के गांव कोरोना के इस दौर में देश के विकास की कुंजी साबित हो सकते हैं। हमें अवसर को पहचानने और उसे भुनाने की दिशा में आगे बढ़ना होगा।

दशकों में बनाई संपत्ति लालच की वेदी पर स्वाहा

श्रीचंद हिंदुजा :दशकों से बनाई संपदा को लालच की वेदी पर स्वाहा करने की तैयारी

श्यामल मजूमदार

हिंदुजा परिवार ने हमेशा एक खुशहाल परिवार की कहानी पेश की है, जहां चार भाई, उनकी पत्नियां, बच्चे और पोते-पोती एक चट्टान की तरह एकजुट हैं। बीते वर्षों के दौरान चारों भाई सार्वजनिक तौर पर यह भी कह चुके हैं कि वे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की तरह हैं। उनके शरीर चार हैं, लेकिन आत्मा एक है। हालांकि जहां तक उनके कारोबारी संबंधों का सवाल है, अब यह पटकथा एक अलग मोड़ ले चुकी है।

ऐसा लगता है कि सभी भाइयों ने चार शरीर, एक आत्मा के सिद्धांत को कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया। इतना अधिक कि ब्रिटेन के दूसरे सबसे धनी और 20 अरब डॉलर से अधिक संपत्ति के मालिक परिवार की उत्तराधिकार योजना महज एक पत्र तक सीमित थी। उन सभी ने इस पत्र पर 2014 में हस्ताक्षर किए थे, जिसमें कहा गया कि (किसी एक भाई के नाम संपत्ति सभी की है।) इस परिवार की न कोई वसीयत थी, न अन्य कोई बाध्यकारी दस्तावेज, न परिवार का संविधान। केवल एक पत्र था। इस वजह से एक बड़े वकील को कहना पड़ा कि यह मामला इससे अधिक हास्यास्पद नहीं हो सकता था। सभी भाई अपनी सेवानिवृत्ति की उम्र से काफी आगे पहुंच चुके हैं। सबसे बड़े श्रीचंद 84 साल के हैं, गोपीचंद 80, प्रकाश 75 और अशोक 70 साल के हैं। हालांकि हिंदुजा परिवार की तीसरी पीढ़ी समूह की कंपनियों की अगुआई कर रही है, जिनमें से ज्यादातर लड़के हैं। मगर एक पत्र अच्छी उत्तराधिकार योजना का सबूत नहीं है।

इस तरह की व्यवस्था से कुछ बड़ी दिक्कतों का दस्तक देना तय था। पहली दिक्कत हाल में उस समय आई, जब समूह के (मौजूदा प्रमुख) माने जाने वाले श्रीचंद हिंदुजा ने इस पत्र की कानूनी शुचिता को चुनौती दी। श्रीचंद ने चार साल पहले भी साफ किया था कि पत्र उनकी अभिलाषाओं को नहीं दर्शाता है और परिवार की संपत्ति का बंटवारा होना चाहिए। ब्रिटेन की अदालत में सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि परिवार के सदस्यों के बीच हिंदुजा बैंक के नियंत्रण को

वीन हिंदुजा:बैंक हड़पने के लिए कलह

लेकर स्विटजरलैंड में मुकदमा चल रहा है। यह बैंक केवल श्रीचंद के नाम है। परिवार के सदस्यों के बीच जर्सी में भी कानूनी मामले चल रहे हैं। हालांकि वजहों का पता नहीं है, मगर तीन अन्य भाई अपने इस बात पर अड़े हैं कि (हर चीज हर किसी की है और कोई भी चीज किसी एक की नहीं है।) हालांकि ऐसा लगता है कि वे मुख्य रूप से इस बात से खफा हैं कि श्रीचंद ने अपने प्रतिनिधि के रूप में बेटी को नियुक्त कर दिया है।

दरअसल तीसरी पीढ़ी को स्वामित्व का हस्तांतरण काफी पहले हो जाना चाहिए था क्योंकि इस समय केवल लड़के ही बड़ी भूमिका में हैं और केवल श्रीचंद हिंदुजा की बेटियां ही समूह के कारोबार में हाथ आजमा रही हैं।

कंपनियों का इतिहास बताता है कि कैसे संस्थापकों ने उद्यम शुरू करने और उन्हें बनाने में प्रशंसनीय कार्य किया, मगर संगठन को छोड़ने और उसे किसी दूसरे अगुआ के हाथ में सौंपकर दूसरे चरण की वृद्धि को मंजूरी देने के स्तर पर खराब काम किया। भारतीय उद्यमों में खराब उत्तराधिकार योजना के असंख्य उदाहरण हैं। इनमें पिताओं और पुत्रों के बीच अदालती झगड़ा (रैनबैक्सी के परविंदर सिंह बनाम भाई मोहन सिंह), भाइयों और चचेरे भाइयों के बीच कानूनी विवाद (मोदी परिवार) और यहां तक कि सास और बहुओं के बीच के विवाद (मफतलाल मामला) शामिल हैं। इससे यह साफ होता है कि इन कंपनियों में से ज्यादातर इसलिए डूब गईं क्योंकि उनके मालिक परिवार खुद अपना विवाद नहीं सुलझा पाए।

बहुत से प्रवर्तक परिवार उस चर्चा में उलझ जाते हैं, जो (लेकिन हमने हमेशा ऐसे ही किया है)के साथ शुरू होती है। वे यह नहीं समझते कि तेजी से बदलती दुनिया में परंपरागत तरीका काम नहीं करता है। उदाहरण के लिए ज्यादातर परिवारों ने हर उत्तराधिकारी पीढ़ी में सबसे बड़े पुरुष को नियंत्रण स्वामित्व और सीईओ का पद दिया है। उन्होंने अन्य उम्मीदवारों के बारे में विचार भी नहीं किया।

हार्वर्ड बिज़नेस रिव्यू के एक अध्ययन में इटली के एंटीनोरी परिवार का उदाहरण दिया गया है, जिसने परंपरागत से इतर तरीका अख्तियार करने का साहस दिखाया। परिवार ने शराब बनाने के अपने कारोबार का स्वामित्व और अगुआई 25 पीढ़ियों के हाथों से गुजरने के बाद स्वामित्व को तीन बेटियों के बीच बराबर बांट दिया और कारोबार की अगुआई को प्रत्येक बेटी की काबिलियत के मुताबिक बांट दिया। वे ऐसा कुछ हद तक इसलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने इस पूर्व धारणा को हटा दिया कि कैसे उत्तराधिकार दिया जाता है और नए सिरे से शुरुआत की।

परिवार के स्वामित्व वाले सबसे अधिक कारोबारों की संख्या के लिहाज से भारत पूरे विश्व में तीसरे पायदान है। हर कोई यह तो कह देता है कि उत्तराधिकार योजना परिवार के स्वामित्व वाले उद्यमों की कार्यप्रणाली के डीएनए में होनी चाहिए, मगर पारिवारिक कारोबारों में इस चीज पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। वे उत्तराधिकार योजना की अहमियत और उसकी कई पीढ़ियों का कारोबारी ढांचा खड़ा करने और परिवार की विरासत बरकरार रखने में भूमिका को कम करके आंकते हैं।

असल में भारत में 75 फीसदी से अधिक कंपनी बोर्ड उत्तराधिकार के मुद्दे पर चर्चा तक नहीं करते हैं। ज्यादातर मुख्य कार्याधिकारी अपनी जगह लेने के लिए किसी के बारे में सोच भी नहीं पाते हैं। अगर उन्हें किसी को चुनना होता है तो वे अपनी जगह अपने जैसे ही व्यक्ति को बैठाने के बारे में विचार करते हैं।

इस तरह के माहौल में, जब परिवार का झगड़ा सामने आता है और परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति का बंटवारा होता है तो कई दशकों में बनाई गई संपत्ति लालच की वेदी पर स्वाहा हो जाती है। यह संभव है कि हिंदुजा और अन्य बहुत से परिवार के स्वामित्व वाले कारोबार उत्तराधिकार योजना के बारे में सीखें।

राफेल के आने से कांग्रेस में मातम का माहौल बोले डॉ.नरोत्तम मिश्रा

भोपाल, एएनआइ। राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप भारत पहुंच गई है। इसे लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बगैर नाम लिए कांग्रेस पर हमला बोला है।

समाचार एजेंसी एएनआइ के अनुसार उन्होंने कहा कि आज राफेल की गर्जन से हिंदुस्तान का आसमान और देश का माथा गौरव से गौरवान्वित होगा। मातम होगा तो केवल तीन जगह चीन, पाकिस्तान और उनके यहां जो सुबह से ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग रोज सुबह उठकर कभी सेना का मनोबल गिराते हैं। कभी देश के सम्मान और स्वाभिमान को आहत करते हैं, अच्छा होगा अगर ऐसे लोग किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लें।

हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि यहां पांच राफेल लड़ाकू विमानों का आगमन ऐतिहासिक रहेगा। विज ने समाचार एजेंसी एएनआइ से कहा, लड़ाकू विमानों के किंग अंबाला पहुंचने से लोगों में उत्साह है। लोगों को राफेल फाइटर जेट्स के आने का इंतजार था। यदि कोरोना वायरस नहीं होता , तो वे उत्सव के साथ लड़ाकू विमानों का स्वागत करते। यह रक्षा की दृष्टि से एक बड़ी उपलब्धि है। हमारे दुश्मनों के लिए, सिर्फ राफेल नाम ही उन्हें डराने के लिए काफी है।

2016 में भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमानों का सौदा किया था

बता दें कि 2016 में भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमानों का 60 हजार करोड़ रुपये में सौदा किया था। यह अब तक सबसे बड़ा रक्षा सौदा है। मौजूदा वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया तब उपसेना प्रमुख थे और उन्होंने इस सौदे में भारतीय दल का नेतृत्व किया था। भारत ने राफेल में अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ बदलाव भी किए हैं। यह विमान पहले मई में ही भारत आने वाले थे, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसमें देरी हो गई है। राफेल विमानों की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए इसे फ्रांस निर्मित हैमर मिसाइल लगाने की तैयारी हो रही है। ये मिसाइल 60 से 70 किमी की दूरी पर भी मजबूत से मजबूत लक्ष्य को ध्वस्त करने में सक्षम है।लोगों को याद है कि भारत में बने छोटे से नेट विमानों ने कैसे दुश्मन के छक्के छुड़ाए थे फिर ये तो तकनीक सम्राट राफाल है।

बुरे वक्त में देश की अर्थव्यवस्था को सांसे दे रहे भारत के गांव

नीता भल्ला

भारत में लॉकडाउन हटाए हुए डेढ़ महीने से ज्यादा समय हो चुका है. सरकार ने अर्थव्यवस्था की खराब होती हालत को देखते हुए अनलॉक फेज एक और दो में आर्थिक गतिविधियों को लगभग पूरी तरह खोल दिया है. भारत की अर्थव्यवस्था अब वापस पटरी पर लौटती दिख रही है, सरकार और आरबीआई के ताजा संकेतों को देखें तो इसका साफ पता चलता है. इसके अलावा हाल ही में गूगल की कोविड-19 मोबिलिटी रिपोर्ट आयी है. ये इशारा कर रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था वापस लॉकडाउन से पहले की स्थिति की तरफ तेजी के साथ बढ़ रही है. गूगल की ये रिपोर्ट 131 देशों के लिए निकाली गई है. इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे कड़ा और लंबा लॉकडाउन लगाने के बाद भी भारत उन टॉप 50 देशों में शुमार है जिनकी अर्थव्यवस्था ज्यादा तेजी के साथ सामान्य स्थित की तरफ बढ़ती दिख रही है.

गूगल की ओर से जुटाई गई जानकारी के अुनसार खुदरा, किराना, फार्मा, ट्रांसपोर्ट और बैंकिंग जैसे सेक्टर कोरोना काल से एकदम पहले की स्थिति की ओर तेजी से बढ रहे हैं. साथ ही ईंधन, बिजली की खपत और खुदरा वित्तीय लेन-देन में बढ़ोत्तरी को भी अर्थव्यवस्था के सामान्य होने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है. लॉकडाउन के दौरान देश में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत 2007 के बाद से सबसे कम हो गई थी, लेकिन अब आंकड़े बताते हैं कि इसमें तेजी से सुधार हो रहा है. बीते जून में जून 2019 के मुकाबले तेल की खपत 88 फीसदी तक पहुंच गई है.

बीते अप्रैल में लॉकडाउन के दौरान वाणिज्यिक और औद्योगिक गतिविधियों में गिरावट आने से बिजली की मांग साल भर पहले की तुलना में करीब 25 प्रतिशत कम रही थी. लेकिन अब आंकड़े काफी उत्साहित करने वाले हैं. केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में बिजली की उच्चतम मांग बीती दो जुलाई को 170.54 गीगावाट दर्ज की गई, जो जुलाई 2019 के 175.12 गीगावाट से महज 2.61 प्रतिशत ही कम है.

लॉकडाउन हटने के बाद बीते जून में वस्तु एवं सेवाकर यानी जीएसटी के संग्रह में भी तेजी आई है. वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार जून में कोरोना वायरस महामारी के बीच केंद्र सरकार का जीएसटी संग्रह 90,917 करोड़ रुपये रहा है. यह जून 2019 की तुलना में

91 फीसदी है. बीते मई में सरकार को जीएसटी से 62,009 करोड़ रुपये और अप्रैल में महज 32,294 करोड़ रुपये का राजस्व ही मिल सका था.

औद्योगिक उत्पादन और विनिर्माण क्षेत्र से भी राहत की खबर आ रही है. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के आंकड़ों के मुताबिक बीते अप्रैल में औद्योगिक उत्पादन में गिरावट 60 फीसदी तक पहुंच गयी थी, जो मई और मध्य जून तक 35 फीसदी से नीचे आ गयी है. इसी तरह विनिर्माण क्षेत्र में बीते अप्रैल में गिरावट करीब 68 फीसदी तक पहुंच गयी थी. लेकिन आईआईपी के आंकड़ों के मुताबिक मई और मध्य जून तक यह गिरावट घटकर 40 फीसदी से नीचे दर्ज की गयी है.

द हिंदू बिजनस लाइन के सीनियर डिप्टी एडिटर शिशिर सिन्हा एक और आंकड़ा भी बताते हैं जिससे आर्थिक गति का अनुमान लगाया जा सकता है. वे बताते हैं, 'हम बिलटी यानी ई बे रसीद के जरिये भी स्थिति के सुधरने का अनुमान लगा सकते हैं. ई बे रसीद तब जारी की जाती है जब कोई सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक ही राज्य में एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है. इससे पता चलता है कि सामान पर टैक्स दिया गया है या नहीं. इस समय ई बे रसीद जारी होने की संख्या तकरीबन (कोविड-19 महामारी से) पहले वाली स्थिति में पहुंच गयी है. पहले 20 से 25 लाख ई बे प्रतिदिन जारी होते थे.'

शिशिर सिन्हा यह भी कहते हैं कि महंगाई दर की स्थिति से भी जाना जा सकता है कि अर्थव्यवस्था का चक्का किस तरह से घूम रहा है. उनके मुताबिक महंगाई दर सीधे-सीधे सप्लाई और मांग पर निर्भर करती है. इससे जुड़े आंकड़े भी बताते हैं कि अर्थव्यवस्था थोड़ी सी पहले वाली स्थिति की तरफ बढ रही है.

भारत की जीडीपी को देखें तो इसमें सेवा क्षेत्र की करीब 57 फीसदी और औद्योगिक क्षेत्र की करीब 30 फीसदी हिस्सेदारी है. इसके बाद कृषि क्षेत्र आता है जिसकी जीडीपी में हिस्सेदारी तकरीबन 13 फीसदी है. बीते अप्रैल में जब देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने शुरू हुए तो आर्थिक मामलों के कई जानकारों का कहना था कि अर्थव्यवस्था को बचाने में ग्रामीण भारत बड़ी भूमिका निभाने वाला है.

ऐसा कहने के पीछे की वजह यह थी कि जिस तरह से शहरी इलाकों में कोविड के मामले तेजी से सामने आ रहे थे उसे देखते हुए साफ था कि सेवा क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्रों की रफ्तार बहुत धीमी रहने वाली है. ऐसे में सिर्फ कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र था, जो अर्थव्यवस्था को सहारा दे सकता था. कृषि क्षेत्र से उम्मीद इसलिए थी क्योंकि ग्रामीण भारत में कोरोना का प्रभाव बेहद कम होने की वजह से वहां रबी की फसल की कटाई सामान्य रूप से चल रही थी. इसके अलावा रबी की फसल को लेकर जो आंकड़े सामने आ रहे थे, वे भी उत्साहित करने वाले थे. कृषि वर्ष 2019-20 में अनाज का रिकॉर्ड 30 करोड़ टन उत्पादन हुआ है. जानकार कहते हैं कि इसके बाद जब केंद्र और राज्य सरकारों ने किसानों को लॉकडाउन की मार से बचाने के लिए राहत योजनायें चलाई तो इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को और फायदा हुआ जिससे वहां से अर्थव्यवस्था को बल मिलने की उम्मीद और ज्यादा हो गई.

उत्तर प्रदेश के कई जिलों के किसानों ने यह बात कही कि सरकार की नीतियों और फसल कटाई के समय से होने की वजह से उन्हें कोरोना वायरस संकट के दौरान कोई खास परेशानी नहीं हुई. किसानों का कहना था कि केंद्र द्वारा 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' के तहत मिलने वाले दो हजार रुपए की दो किश्तों को तत्काल उनके अकाउंट में डालना, उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन पाए लोगों को तीन सिलेंडर मुफ्त देना, समर्थन मूल्य ब ?ाना और राशन में हर महीने चना और अनाज मुफ्त देने के चलते उन्हें आर्थिक तौर पर जरा भी परेशानी नहीं उठानी पड़ी.

जानकार कहते हैं कि इन्हीं सब वजहों के चलते ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आर्थिक स्थिति पहले से बुरी न होकर कुछ बेहतर ही हुई है. इस वजह से देशव्यापी लॉकडाउन के हटते ही वहां आर्थिक गतिविधियां तेज रफ्तार में चलने लगीं. अगर पिछले डेढ़ महीने के आकड़ों पर नजर डालें तो इसका स्पष्ट पता चलता है. जून महीने में ग्रामीण क्षेत्र में ऑटो इंडस्ट्री के आंकड़े काफी चौंकाने वाले रहे हैं. इस दौरान यहां ट्रैक्टर की बिक्री में रिकॉर्ड उछाल देखने को मिला है.

सोनालिका समूह के कार्यकारी निदेशक रमन मित्तल मीडिया से बातचीत में बिक्री के आंकड़ों की जानकारी देते हुए कहते हैं, 'यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि सोनालिका ट्रैक्टर्स इस कठिन समय में अधिकतम वृद्धि दर्ज करने वाली एकमात्र कंपनी है. हमने 15,200 ट्रैक्टरों के साथ बीते जून में दमदार प्रदर्शन किया है, इस साल जून में हुई बिक्री ने अब तक का हमारा उच्चतम स्तर छुआ है.'

ऐसा ही कुछ हाल महिंद्रा एंड महिंद्रा का भी रहा है. जून में महिंद्रा ट्रैक्टर्स की बिक्री में 12 फीसदी का उछाल दर्ज किया गया है. कंपनी ने इस दौरान रिकॉर्ड 35,844 ट्रैक्टर बेंचे हैं. महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड में फार्म इक्विपमेंट सेक्टर के प्रमुख हेमंत सिक्का एक साक्षात्कार में बताते हैं, 'बीते जून में महिंद्रा ट्रैक्टर की बिक्री के आंकड़े अब तक के हमारे दूसरे सबसे बड़े आंकड़े हैं. दक्षिण-पश्चिम मानसून के समय पर आने, रबी की रिकॉर्ड फसल, कृषि को बढावा देने के लिए सरकार द्वारा चलायी गयीं योजनाओं के कारण किसान इस समय खासे उत्साहित हैं.'

केवल ट्रैक्टर ही नहीं, ऑटो क्षेत्र की अन्य कंपनियों को भी ग्रामीण भारत ने बड़ी राहत दी है. बाजार में चल रहे उतार-चढ़ाव पर नजर रखने वाली कंपनियां नोमुरा, एमके ग्लोबल और मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैक्टर के अलावा दोपहिया, तिपहिया और चार पहिया वाहनों की बिक्री में भी शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में काफी ज्यादा बढ़ोत्तरी देखी गयी है.

गूगल की कोविड-19 मोबिलिटी रिपोर्ट यह दावा भी करती है कि लॉकडाउन हटने के बाद भारत में यूरोप के 17 देशों से कहीं ज्यादा चीज-सामान की खपत हो रही है. अर्थ जगत के जानकार इसके पीछे भी ग्रामीण क्षेत्र का बड़ा योगदान मानते हैं.

'तेज़ी से बिकने वाली उपभोक्ता वस्तुयें' बनाने वाली एफएमसीजी कंपनियों के आंकड़े बताते हैं कि शहरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादों की मांग कई गुना बढ़ी है. मार्केट रिसर्च से जुड़ी कंपनी नील्सन की हाल में आयी रिपोर्ट की मानें तो बीते मई में ही ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री कोविड से पहले वाली औसत बिक्री के 85 फीसदी तक पहुंच गयी थी. जबकि शहरी बाजार में यह आंकड़ा 70 फीसदी पर था.

खाने-पीने के उत्पाद बनाने वाली कई कंपनियों जैसे पारले, ब्रिटेनिया ने भी लॉकडॉन के दौरान और उसके बाद अपने उत्पादों की बिक्री कई गुना बढ़ने की बात कही थी. देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान पारले-जी ने पिछले 82 सालों की बिक्री का रिकॉर्ड तोड़ दिया था. पारले प्रोडक्ट्स के वरिष्ठ प्रमुख मयंक शाह मीडिया से बातचीत में कहते हैं, 'हमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मजबूत डिमांड मिल रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में डिमांड पहले से दोगुनी है.' मयंक मानते हैं कि कोविड के दौर में ग्रामीण अर्थव्यवस्था शहर की तुलना में बेहतर स्थिति में है.

मेक इन इंडिया ही है चीन से मुकाबले की सटीक युद्धनीति

डॉ जसपाली चौहान

आत्मनिर्भर तो हम भारतीय परिश्रम, भारतीय प्रतिभा तथा स्थानीय स्तर पर बने लोकल उत्पादों के दम पर ही बन सकते हैं। तभी हमारी आयात पर निर्भरता कम हो पाएगी। हमें मेक इन चाइना का जवाब मेक इन इंडिया से देना होगा। हमें लोकल के लिए वोकल बनना ही होगा। देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना ही होगा।

आत्मनिर्भरता आज समय की मांग बन चुकी है। हम भी आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। हम स्वदेशी का आंदोलन चलाते हैं, विदेशी का बहिष्कार करते हैं और इस तरह से हो जाना चाहते हैं आत्म निर्भर। परन्तु आत्मनिर्भरता की हकीकत पर जब हम विचार करते हैं, तो पाते हैं कि यह कार्य इतना सरल भी नहीं है, क्योंकि हम दूसरों पर कुछ ज्यादा ही निर्भर हैं। हमारा दवाई उद्योग, हमारे चिकित्सा-उपकरण, हमारा सौर-ऊर्जा उद्योग,मोबाइल और मोटर पार्ट्स का उद्योग और खिलौना उद्योग सहित विभिन्न चीजों में हम पूरी तरह से चीन पर निर्भर हैं। इसके बाद हमारे रत्न- आभूषण, भारी मशीनें, स्टील, प्लास्टिक, वनस्पति तेल जैसे उत्पादों के लिए हम संयुक्त अरब, जापान, दक्षिण कोरिया और मलेशिया पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में कैसे बन पाएंगे आत्मनिर्भर हम ? हम स्वयं उत्पाद करते नहीं है।

दूसरों के भरोसे रहते हैं। विदेशी को तवज्जो देते हैं। उसका देशज विकल्प ढूंढना नहीं चाहते हैं। अपने उत्पादन को हीन मानते हैं। आयातित विदेशी वस्तुओं के साथ अपनी प्रतिष्ठा को जोड़कर चलते हैं। इसलिए लोकल के लिए वोकल कभी बने नहीं, फिर कैसे दे पाएंगे अपनी अर्थव्यवस्था को गति ? एक बड़ी चुनौती ब्राण्ड के मोर्चे पर भी है। गुणवत्ता के मामले में आज भी दुनिया हमारे उत्पादों पर भरोसा नहीं करती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को हम अपेक्षित संख्या में आकर्षित नहीं कर पाए हैं। उन्हें उचित माहौल नहीं दे पाए हैं, जिससे कि वह भारत में आकर उत्पाद कर सके। फिर कैसे मिल पाएगा भारतीय ब्रांड को वैश्विक मंच ? वर्तमान सरकार ने उन्हें उचित माहौल देखकर आकर्षित करने के लिए ऋण सुविधाओं को काफ़ी सरल बनाया है।

आत्म निर्भरता की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग धंधों का होता है। यह ईकाइयां बड़े पैमाने पर रोजगार मुहैया करवाती है, जिससे आम आदमी के हाथ में पैसा आता है तथा उसकी क्रय

शक्ति बढ़ती है और फिर बाजार में मांग उत्पन्न होती है। यह अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती है, परंतु अभी तक यह ईकाइयां महंगी ब्याज दर तथा ऋण व्यवस्था के कठोर नियमों के कारण विशेष योगदान नहीं दे पाई। सरकार ने अब इनके लिए भी सस्ती ब्याज दरों पर सरल नियमों के साथ गारंटी मुक्त ऋण की व्यवस्था की है । ताकि ये ईकाइयां अपना उत्पाद बढ़ाएं, जिससे स्थानीय विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा मिल सके। बड़ा राहत पैकेज भी इनको दिया है, जो इन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की ओर से उठाया गया एक महत्वपूर्ण एवं सराहनीय कदम है।

यह राहत पैकेज हमारे किसान, श्रमिक, लघु उद्यमी, स्टार्ट अप्स से जुड़े नौजवान सभी के लिए नए अवसरों का दौर लेकर आएगा। नवाचार की दृष्टि से भी हम अच्छी स्थिति में नहीं हैं। यह कमी तभी पूरी होगी जब हम विश्व अर्थव्यवस्था के साथ कदम बढ़ाएंगे। यद्यपि अतीत में महामारियों ने ही नवाचार को गति देने का काम किया है और नए विचारों के साथ बदलाव को मुमकिन बनाया है। करोनाकाल में वर्क फॉम होम जैसी व्यवस्था हमारे देश में भी एक सामान्य सी बात हो गई है। यह व्यवस्था आर्थिक दृष्टि से किफायती भी है।हम सचमुच में आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो हमें सर्वप्रथम आयातित वस्तुओं का देशज विकल्प ढूंढना होगा। आयातित प्रत्येक वस्तु का उत्पादन स्वयं अपने देश में करना होगा।

बेशक हम इसके कुशल उत्पाद में सक्षम हो या न हों। देश को उन क्षेत्रों में भी संसाधन उपलब्ध कराने होंगे, जहां उत्पादकता कम है तथा कम लागत में गुणवत्तापूर्ण उत्पादन करने वाले क्षेत्रों को और अधिक संसाधन मुहैया कराने होंगे ताकि लाभ की स्थिति बनी रहे। हम विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात करते हैं, परंतु हम तुरंत प्रभाव से विदेशी सामान का शत-प्रतिशत बहिष्कार भी आज की परिस्थिति में नहीं कर सकते हैं। हमें तब तक वैश्विक आपूर्ति संख्या का हिस्सा बने रहना होगा जब तक कि यह हमारी उत्पादकता में इजाफा करते हैं।

अन्ततः-आत्मनिर्भर तो हम भारतीय परिश्रम, भारतीय प्रतिभा तथा स्थानीय स्तर पर बने लोकल उत्पादों के दम पर ही बन सकते हैं। तभी हमारी आयात पर निर्भरता कम हो पाएगी। हमें मेक इन चाइना का जवाब मेक इन इंडिया से देना होगा। हमें लोकल के लिए वोकल बनना ही होगा। देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना ही होगा। परंतु भारत उत्पाद का हब तभी बन पाएगा, जब देश का प्रत्येक व्यक्ति यह तय करेगा कि हम भारत में ही बनी चीजों का उपयोग करेंगे। तभी हमारी अर्थव्यवस्था को गति मिल पाएगी। यदि हमारे अंदर संकल्प शक्ति आत्म बल और आत्मविश्वास है तो हम अवश्य ही आत्मनिर्भर बनेंगे। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में वैश्विकरण का बहिष्कार नहीं है अपितु दुनिया के विकास में मदद की मंशा है। हमारी संस्कृति तो वसुधैव कुटुंबम की संकल्पना में विश्वास रखती है और भारत जो कि दुनिया का ही हिस्सा है, ऐसे में उसकी प्रगति दुनिया की प्रगति में योगदान देगी।

(संयोजिका भाजपा शिक्षा प्रकोष्ठ,दिल्ली.)

सदियों की गर्द को ठोकर मारकर अपना जूता फाड़ लेने वाला कलम का मुंशी

धनपत राय श्रीवास्तव उर्फ मुंशी जी प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है, पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुरता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियाँ उभर आई हैं, पर घनी मूँछें चेहरे को भरा-भरा बतलाती हैं।

पाँवों में केनवस के जूते हैं, जिनके बंद बेतरतीब बँधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं।

दाहिने पाँव का जूता ठीक है, मगर बाएँ जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अँगुली बाहर निकल आई है।

मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ–फोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है, तो पहनने की कैसी होगी ? नहीं, इस आदमी की अलग-अलग पोशाकें नहीं होंगी–इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है, वैसा ही फोटो में खिंच जाता है।

मैं चेहरे की तरफ़ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है, मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और अँगुली बाहर दिख रही है ? क्या तुम्हें इसका ज़रा भी अहसास नहीं है ? ज़रा लज्जा, संकोच या झेंप नहीं है ? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अँगुली ढक सकती है ? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है! फोटोग्राफर ने जब `रेडी-प्लीज़' कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुसकान लाने की कोशिश की होगी, दर्द के गहरे कुएँ के तल में कहीं पड़ी मुसकान को धीरे-धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही `क्लिक' करके फोटोग्राफर ने `थैंक यू' कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुसकान। यह मुसकान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है!

यह कैसा आदमी है, जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिचा रहा है, पर किसी पर हँस भी रहा है!

फोटो ही खिचाना था, तो ठीक जूते पहन लेते, या न खिचाते। फोटो न खिचाने से क्या बिगड़ता था। शायद पत्नी का आग्रह

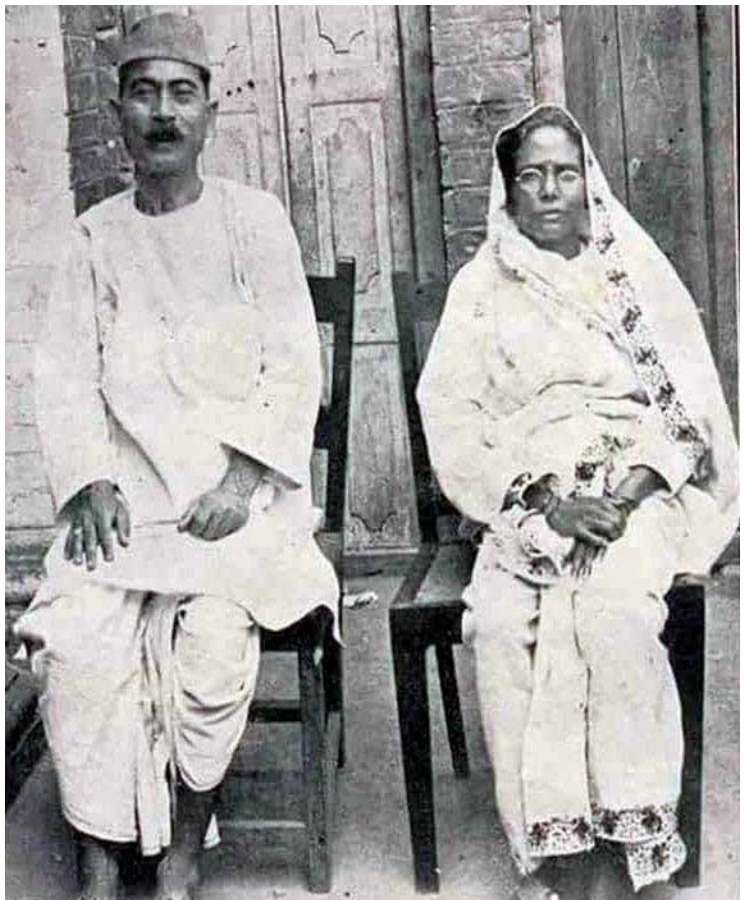

रहा हो और तुम, `अच्छा, चल भई' कहकर बैठ गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी `ट्रेजडी' है कि आदमी के पास फोटो खिचाने को भी जूता न हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते-देखते, तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आँखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है।

तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। समझते होते, तो किसी से फोटो खिचाने के लिए जूते माँग लेते। लोग तो माँगे के कोट से वर-दिखाई करते हैं। और माँगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिचाने के लिए तो बीवी तक माँग ली जाती है, तुमसे जूते ही माँगते नहीं बने! तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए! गंदे-से-गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है!

टोपी आठ आने में मिल जाती है और जूते उस ज़माने में भी पाँच रुपये से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते परपचीसों टोपियाँ न्योछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी, जितनी आज चुभ रही है, जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास-सम्राट, युग-प्रवर्तक, जाने क्या-क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है!

मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। यों ऊपर से अच्छा दिखता है। अँगुली बाहर नहीं निकलती, पर अँगूठे के नीचे तला फट गया है। अँगूठा ज़मीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अँगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अँगुली दिखती है, पर पाँव सुरक्षित है। मेरी अँगुली ढँकी है, पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम परदे का महत्व ही नहीं जानते, हम परदे पर कुर्बान हो रहे हैं!

तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो! मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह नहीं खिचाऊँ, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे।

तुम्हारी यह व्यंग्य-मुसकान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका ? कौन सी मुसकान है यह ?

–क्या होरी का गोदान हो गया ?

–क्या पूस की रात में नीलगाय हलकू का खेत चर गई ?

–क्या सुजान भगत का लड़का मर गया; क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते ?

नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफ़न के चंदे की शराब पी गया। वही मुसकान मालूम होती है।

मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ। कैसे फट गया यह, मेरी जनता के लेखक ?

क्या बहुत चक्कर काटते रहे ?

क्या बनिये के तगादे से बचने के लिए मील-दो मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे ?

चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभनदास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने-आने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा- `आवत जात पन्हैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम।'

और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था–`जिनके देखे दुख उपजत है, तिनको करबो परै सलाम!'

चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया ?

मुझे लगता है, तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज़ जो परत-पर-परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार-मारकर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आज़माया।

तुम उसे बचाकर, उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियाँ पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर, घूमकर भी तो चली जाती है।

तुम समझौता कर नहीं सके। क्या तुम्हारी भी वही कमज़ोरी थी, जो होरी को ले डूबी, वही `नेम-धरम' वाली कमज़ोरी ? `नेम-धरम' उसकी भी ज़ंजीर थी। मगर तुम जिस तरह मुसकरा रहे हो, उससे लगता है कि शायद `नेम-धरम' तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी!

तुम्हारी यह पाँव की अँगुली मुझे संकेत करती-सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ़ हाथ की नहीं, पाँव की अँगुली से इशारा करते हो ?

तुम क्या उसकी तरफ़ इशारा कर रहे हो, जिसे ठोकर मारते-मारते तुमने जूता फाड़ लिया ?

मैं समझता हूँ। तुम्हारी अँगुली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग्य-मुसकान भी समझता हूँ।

तुम मुझ पर या हम सभी पर हँस रहे हो, उन पर जो अँगुली छिपाए और तलुआ घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकाकर बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो–मैंने तो ठोकर मार-मारकर जूता फाड़ लिया, अँगुली बाहर निकल आई, पर पाँव बच रहा और मैं चलता रहा, मगर तुम अँगुली को ढाँकने की चिंता में तलुवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे ?

मैं समझता हूँ। मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, अँगुली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग्य-मुसकान समझता हूँ!

.- हरिशंकर परसाई की क़लम से

मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लमही गाँव में हुआ था।

शत शत नमन

घनश्याम दास बिड़ला : भारत की औद्योगिक क्रांति के जनक

खुद को व्यापारी नहीं ट्रस्टी मानकर लिखी भारत के विकास की इबारत

अनुराग भारद्वाज

एक जमाना था जब किसी की रईसियत पर तज कसना होता था तो कहते, 'तू कौन सा टाटा-बिड़ला है?' आज हम उसी बिड़ला की बात कर रहे हैं जिसे दुनिया घनश्यामदास बिड़ला (जीडी बाबू) के नाम से जानती है. बिड़ला मारवाड़ी समाज के बनिए होते हैं. गुरचरण दास ने अपनी किताब 'उन्मुक्त भारत' में लिखा है, 'मारवाड़ी जिस इज्जत के हकदार हैं, इस देश ने उन्हें उतनी इज्जत नहीं बख्शी.' बावजूद इसके हिन्दुस्तान के व्यापार पर इनका कब्जा होने की कहानी बहुत ही जबरदस्त है.

'मारवाड़ी' शब्द 'मारू' और 'वाडा' के संयोग से बना है. 'मारवाडी' का मतलब है 'मौत की जमीन'. यूं तो मारवाड़ी राजस्थान के जोधपुर संभाग को कहते हैं पर मारवाड़ी दरअसल राजस्थान के शेखावाटी इलाके से ताल्लुक रखते हैं. मारवाड़ियों के सफल व्यापारी होने पर कई रिसर्च की गयी हैं. थॉमस टिमबर्ग ने तो मारवाड़ियों पर डॉक्टरी की है. उनकी सफलता के कई कारण बताये जाते हैं - जैसे मजबूत पारिवारिक संगठन, जोखिम लेने की हिम्मत, पैसे की समझ आदि.

ये सारी बातें सही हैं, पर जोखिम लेना और पैसे की समझ उन्हें कैसे आई? तो इसके पीछे तर्क यह है कि शेखावाटी में जीवन बहुत कठिन है. हर संसाधन की कमी है और सबसे बड़ा संसाधन पानी और भी कम है. मारवाड़ियों ने पानी का संचयन किया और सही तरीके से इस्तेमाल किया. संसाधनों को सहज कर रखने की सोच पीढ़ी दर पीढ़ी इनके अंदर रच-बस गयी. इसी सोच से इन्होंने पैसे को सहेजा और सही जगह इस्तेमाल किया.

घनश्याम दास बिड़ला का जन्म पिलानी में हुआ था. उनका खानदानी पेशा पैसा ब्याज पर देना था. शेखावाटी के मारवाड़ी जयपुर रियासत जैसी बड़ी और कई छोटी-मोटी रियासतों के राजाओं को ब्याज पर पैसा देते थे. एसएन तिवारी ने अपनी किताब 'फ्रीडम स्ट्रगल एंड रोल ऑफ कम्युनिटीज' में मारवाड़ियों पर लिखा है कि जब राजाओं को युद्ध लड़ने के लिए पैसे की जरूरत होती थी तो शेखावाटी के मारवाड़ी ब्याज पर पैसा देते थे. बाद में जब यहां के राजाओं और ठाकुरों ने अंग्रेजों की सरपरस्ती कुबूल कर ली और लड़ाइयां बंद हो गयीं तब मारवाड़ी उठकर उन जगहों पर जा बसे जहां व्यापार की संभावनाएं होती थीं.

बड़े शहर जाकर व्यापार सीखने की मारवाड़ियों की रवायत को घनश्याम दास ने भी निभाया और पिलानी से कोलकाता चले आये. यहां वे नाथूराम सराफ के बनाये हुए हॉस्टल में रहने लगे. उस हॉस्टल में कई और मारवाड़ी बच्चे थे. सब एक-दूसरे से अपने अनुभव साझा करते और सीखते. 16 साल की उम्र तक आते-आते उन्होंने अपनी ट्रेडिंग फॉर्म खोल ली और पटसन (जूट) की दलाली में लग गए. पहले विश्व युद्ध में पटसन और कपास की भारी मांग के चलते जीडी बाबू ने खूब मुनाफा कमाया. अंग्रेज व्यापारी बिड़ला से नफरत करते थे. उन्होंने पटसन के व्यापार पर एकतरफा कब्जा कर लिया था और यूरोप के कारखानों को ऊंचे दामों पर पटसन बेचते थे. इससे बचने के लिए अंग्रेजों ने मुद्रा के विनिमयन को अपने हक में कर लिया तब बिड़ला ने 'हिंदुस्तान के सोने और स्टर्लिंग की लूट' की बात कहकर पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया था. कई बार अंग्रेज कारोबारियों ने उनके व्यापार को बंद करवाने की कोशिशें की पर हर बार नाकाम रहे.

एक अनुमान के मुताबिक 1939 से 1969 के बीच टाटा की संपत्ति तो सिर्फ आठ गुना बढ़ी थी लेकिन, घनश्याम दास बिड़ला की संपत्ति में 94 गुना का इजाफा हुआ था

हौसले से लबरेज बिड़ला ने तब मैन्युफैक्चरिंग में कदम रखा और 1917 में कोलकाता में 'बिड़ला ब्रदर्स' के नाम से पहली पटसन मिल की स्थापना की. 1939 के आते आते ये फैक्ट्री देश की तेहरवीं सबसे बड़ी निजी फैक्ट्री बन चुकी थी. इसी समय जेआरडी टाटा भी हिंदुस्तान के नक्शे पर उभर रहे थे. एक अनुमान के हिसाब से 1939 से 1969 तक टाटा की संपत्ति 62.42 करोड़ से बढ़कर 505.56 करोड़ (करीब आठ गुना) हो गई थी. उधर घनश्याम दास बिड़ला की संपत्ति 4.85 करोड़ से बढ़कर 456.40 करोड़ यानी करीब 94 गुना हो गयी थी. दोनों ही संपत्ति बना रहे थे पर बिड़ला का मामला दीगर था. उनके साथ न तो कोई पुराना इतिहास था और न ही कोई विरासत. जिस तरह पटसन की दलाली में उन्हें अंग्रेजों से जूझना पड़ा ठीक उसी तरह जब उन्होंने 1958 में हिंडाल्को की स्थापना की तब भी उन्हें अफसरशाही से लड़ना पड़ा.

गुरचरण दास ने लिखा है, '...लोगों को लगता कि बिड़ला ने सरकार की बाहें मरोड़कर व्यापार स्थापित किया है. ये लोग 'हड़ारी कमेटी' की रिपोर्ट का हवाला देते है जिसमें लिखा है कि 1957 से लेकर 1962 तक बिड़ला ने सरकार द्वारा दिए गए कुल लाइसेंसों में से 20 फीसदी पर कब्जा करके व्यापार में एकाधिकार करने की कोशिश की'. गुरचरण आगे लिखते हैं, 'ये गलत बात है क्यूंकि 1945 में उनके पास 20 कारोबारी कंपनियां थी और 1962 तक बिना किसी सरकारी मदद से उन्होंने 150 कंपनियां बना ली थीं. क्या ये एकाधिकार नहीं था?...' उस दौर में वे एक से एक बड़ी फैक्ट्री स्थापित करते जा रहे थे और ऐसा कहा जाता हैं कि उन्ही के डर से लाइसेंस राज और एमआरटीपी जैसे एक्ट लगाये गए थे. वह समाजवाद का दौर था जब किसी पूंजीवादी को ज्यादा उत्पादन करने से रोका जाता था.

बहुत लोगों को लगता है कि उन्हें कांग्रेस सरकार से नजदीकी का फायदा मिला. हकीकत यह है कि नेहरू-गांधी परिवार से उनके ताल्लुकात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे. 20 अप्रैल, 1953 को उन्होंने नेहरू को एक पत्र लिखा था जिसके कुछ अंश इस तरह हैं - '...मेरी कंपनी को कुछ विदेशी प्रस्ताव मिले हैं जिनमें इंग्लैंड की सरकार के साथ ज्वलनशील पदार्थ की फैक्ट्री लगाना और जर्मनी की सरकार के साथ स्टील प्लांट की स्थापना मुख्य है. मेरी उम्र 60 की हो चुकी है. मुझे पैसा कमाने की अब कोई चाह नहीं है. बस इतना चाहता हूं कि उत्पादन बढ़े जिससे देश को फायदा हो. मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या हम इन प्रस्तावों पर आगे बढ़ा सकते हैं? मुझे सरकार से किसी प्रकार की मदद नहीं चाहिए बस इतना बता दीजिये कि आपकी सरकार इस बाबत क्या सोचती है.'

उन्हें सरकार से कोई जवाब नहीं मिला. जीडी बाबू की गांधीजी, मदन मोहन मालवीय, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय और लाल बहादुर शास्त्री से काफी नजदीकी रही. नेहरू बिड़ला को संशय की नजर से देखते थे. इसलिए ही नहीं कि वे सरदार पटेल के करीब थे बल्कि इसलिए भी कि वे विलायत से पढ़कर आये थे, समाजवाद से प्रेरित थे और ठेठ देशज और पूंजीवाद के समर्थक थे. व्यापार के साथ-साथ उन्हें राजनीति में भी दिलचस्पी थी.

1915 में घनश्याम दास बिड़ला गांधीजी के साथ जुड़ गये थे. आजादी के आंदोलन में जीडी की तीनतरफा भूमिका थी. पहला, उन्होंने पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास के साथ मिलकर 'फिक्की' की स्थापना की. दूसरा, आजादी की जंग में उनसे ज्यादा धन किसी ने नहीं लगाया. और तीसरा, 1926 में मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय की पार्टी की तरफ से वे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में गोरखपुर की सीट से चुने गए थे. गांधीजी ने एक जगह लिखा है - 'मेरे कई गुरु रहे और उनमे से एक जीडी भी हैं...' 14 मार्च, 1932 को घनश्याम दास बिड़ला के लाई टेंपलवुड को लिखे पत्र का मजमून कुछ इस प्रकार है, '...सर, मैं आपको भरोसे का व्यक्ति मानता हूं लिहाजा मेरा मानना है कि आप मेरे बारे में जाने. मैं गांधीजी का अनुयायी हूं और एक तरह से उनका 'प्रिय' भी हूं. मैंने उनके आंदोलनों में आर्थिक सहायता की है. हालांकि मैंने कभी 'सविनय अवज्ञा' आंदोलन में सक्रिय भाग नहीं लिया पर सरकार की नीतियों का घोर आलोचक हूं और इसलिए सरकारी तंत्र में मुझे पसंद नहीं किया जाता...'

बावजूद इसके, 1940 में जब ब्रिटेन की महारानी मैरी हिंदुस्तान आयीं तो लार्ड वावेल देश के कुछ नामचीन लोगों से उन्हें मिलवाना चाहते थे. नेहरू ने टाटा का नाम सुझाया था. हालांकि वावेल मारवाड़ियों से ज्यादा प्रभावित नहीं थे, पर उनकी नजर में रानी मैरी को बिड़ला ज्यादा दिलचस्प लगने वाले थे. वावेल लिखते हैं, '...मैं समझता हूं कि रानी को टाटा के बनिस्बत बिड़ला ज्यादा दिलचस्प लगेंगे. उनके पास काफी कुछ कहने को हैं. आप चाहे मारवाड़ियों के तौर-तरीकों के बारे में कुछ भी कहें पर भोजन पर रानी के साथ बिड़ला की बातचीत रानी को पसंद आएगी...'

मेधा कुदसिया ने जीडी बाबू की जीवनी लिखी है. इसमें उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री और घनश्याम बिड़ला के संबंधों का जिक्र किया है कि शास्त्री चाहते थे कि बिड़ला देश में औद्योगिक क्रांति लेकर आयें. शास्त्री चाहते थे कि सरकार का चेहरा तो समाजवाद का ही रहे पर भीतर ही भीतर आर्थिक सुधार की प्रक्रिया भी शुरू हो. गुरचरण दास लिखते हैं कि जो सुधार 1991 में लाये गए थे वे अगर 1965 में लागू हो जाते तो देश का चेहरा कैसा होता! आप को जानकर हैरत होगी कि बिड़ला दुर्गापुर में स्टील प्लांट की स्थापना करना चाह रहे थे और वहां पैसा भी काफी लगा दिया था. फिर न जाने क्या हुआ कि नेहरू ने उनसे यह छीन ले लिया और सरकार ने उस प्लांट की स्थापना की. जीडी बाबू ने इस बात पर कभी नेहरू को माफ नहीं किया.

जीडी बाबू अपने बारे में कम ही बात किया करते. पर जब कभी कुछ अपने बारे में कहना होता तो अप्रत्याशित बात करने से नहीं चूकते थे. मसलन 80 के दशक में एक अंग्रेजी पत्रिका को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वे खुद को एक व्यापारी नहीं मानते. जब उनसे पूछा गया कि क्या हिन्दुस्तान में साम्यवाद पनप सकता है तो उन्होंने साफ मना कर दिया. और जब यह पूछा गया कि उन्हें जीवन में सबसे ज्यादा किसने प्रभावित किया है तो उनका कहना था - 'गांधीजी और विंस्टन चर्चिल.'

भारत में समाजवाद सत्ता की सीढ़ी रहा है। बाद में यही कांग्रेस की नीति बन गई। बरसों तक जब देश घाटे की घाटी पर लुढ़कता रहा तब पीवी नरसिम्हाराव ने देश की आर्थिक विकास यात्रा को नई दिशा दी ।

कर्ज न चुका पाएं तो झूठी शान छोड़ें दिवालिया हो जाएं

बिंदिशा सारंग

पिछले कुछ अरसे में हमने माइकल जैकसन, माइक टायसन और विजय माल्या जैसी हस्तियों के दिवालिया होने या दिवालिया घोषित किए जाने की अर्जी देने की खबरें सुनी हैं। हालांकि किसी व्यक्ति के दिवाला होने की खबरें मुश्किल से ही आती हैं क्योंकि इसके कानून बहुत सख्त हैं और समाज में इससे बदनामी भी होती है। मगर करीब एक सदी पुराने मौजूदा कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति आपका 500 रुपये का उधार भी नहीं लौटा सकता तो आप उसके खिलाफ दिवालियापन का मामला दर्ज करा सकते हैं। यह बात अलग है कि इसकी प्रक्रिया बहुत पेचीदा है।

आरएसएम इंडिया के संस्थापक सुरेश सुराणा ने कहा, दिवालिया होने का मामला वहां बनता है, जहां कोई व्यक्ति अपने कर्ज चुकाने में नाकाम हो जाता है। वैसे किसी को दिवालिया तभी माना जाता है, जब कानूनी तौर पर उसे दिवालिया घोषित किया जाता है।हालांकि ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता, 2016 (आईबीसी) 2 दिसंबर, 2016 को लागू हुई और इसमें व्यक्तिगत दिवालियेपन के लिए भी नियम हैं मगर अभी तक उनकी अधिसूचना जारी नहीं हुई है। पीएसएल एडवोकेट्स ऐंड सॉलिसिटर्स के संस्थापक और प्रबंध साझेदार संदीप बजाज ने कहा, इस समय व्यक्तिगत ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवाला के संबंध में प्रक्रिया प्रेसिडेंसी टाउन्स इन्सॉल्वेंसी ऐक्ट 1909 (कलकत्ता, बंबई और मद्रास के उच्च न्यायालयों में शुरू होने वाली प्रक्रियाओं पर लागू) और प्रॉविंशियल इन्सॉल्वेंसी ऐक्ट 1920 (शेष भारत पर लागू) के हिसाब से चलती है। संहिता के प्रावधानों की अधिसूचना जारी होने के बाद संहिता का खंड 23 निरस्त हो जाएगा और उपरोक्त कानून निष्प्रभावी हो जाएंगे। गौरतलब है कि दोनों ही अधिनियमों में प्रावधान समान हैं।

एनए शाह एसोसिएट्स में पार्टनर गोपाल बोहरा ने कहा, मौजूदा दिवालिया कानून वेतनभोगी और अपना व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के बीच किसी तरह का फर्क नहीं करते। यदि किसी व्यक्ति पर किसी और का कर्ज चढ़ा है तथा वह बिगड़ती वित्तीय स्थिति के कारण कर्ज चुकाने में समर्थ नहीं है तो वह दिवालिया होने के लिए आवदेन कर सकता है.

अगर आपने दिवालिया घोषित किए जाने के लिए आवेदन करने रोक की व्यवस्था है। लेकिन का फैसला कर लिया है तो आपको मौजूदा कानूनों के तहत आप किसी वकील से मिलना होगा, जिसे अदालत में रोक के आदेश के लिए जरूरी दस्तावेज दिखाकर आप आवेदन कर सकते हैं ।

अदालत में प्रस्ताव दायर कर सकें। सुनवाई की तारीख पर अगर इसके बाद न्यायालय यह देखेगा न्यायालय यह पाता है कि आपकी कि आवेदन करने की सभी शर्तें याचिका संतोषजनक है तो वह पूरी की गई हैं या नहीं।उसके आधार न्यायिक आदेश पारित कर पर ही न्यायालय याचिका को मंजूर सकता है, जिससे आप यानी या रद्द कर सकता है। आपकी तरफ ऋणी अनडिस्चार्जड इनसॉल्वेंट से याचिका दायर किए जाने के बन जाएंगे। इसके बाद अगर बाद सुनवाई की एक तारीख घोषित आपकी कोई संपत्ति है तो न्यायालय की जाती है। अदालत एक अंतरिम द्वारा नियुक्त अधिकारी उसकी प्राप्तकर्ता नियुक्त करती है, जो बिक्री करेगा। बिक्री से प्राप्त पैसे आपकी समूची संपत्तियों पर फौरन को ऋणदाताओं के बीच बांटा कब्जा कर लेता है। जाएगा। बोहरा ने कहा, यह बंटवारा

स्वतंत्र विधि सलाहकार और वरीयता क्रम में होगा। सबसे पहले समूह विधि सेंटर फॉर लीगल दिवालिया खर्च, कामगारों का पॉलिसी में रिसर्च फेलो ऐश्वर्या बकाया, सुरक्षित ऋणदाताओं और सतीजा ने कहा, आईबीसी में स्वत- कर्मचारियों का बकाया चुकाया जाएगा। उसके बाद पैसा बचता है तो उसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बांटा जाएगा। अगर दिवालिया व्यक्ति पर पहले का कोई आयकर बकाया है तो उसका भुगतान भी वरीयता क्रम में अन्य ऋणदाताओं के भुगतान के बाद बची रकम से ही होगा। रकम इतनी कम हो कि बांटने के बाद आयकर चुकाने के लिए पैसा ही नहीं बचे तो कर देनदारी अपने आप खत्म हो जाएगी।

जब अदालत में दिवालिया प्रक्रिया चल रही होती है तो आप गुजर-बसर के लिए न्यूनतम राशि की खातिर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यह स्वैच्छिक राहत है, जो हर मामले में अलग-अलग होती है। आखिर में आपको अदालत से पूर्ण भुगतान प्रमाणपत्र लेने की जरूरत होगी। यह वितरण की पूरी प्रक्रिया समाप्त होने पर ही मिलेगा। अदालत यह तय करने के लिए कई मापदंडों पर विचार करती है कि कर्जदार दुर्भाग्यवश दिवालिया हुआ है। वह यह भी देखती है कि कर्जदार ने धोखाधड़ी या बेईमानी तो नहीं की है। इसके बाद बाकी बची देनदारी खत्म कर दी जाती है कर्ज देने वाली संस्था या व्यक्ति दिवालिया व्यक्ति को बकाया चुकाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

अगर आप पर सरकार का बकाया है या आपने कोई वित्तीय धोखाधड़ी की है तो आप सभी ऋणों के संबंध में क्लीन चिट हासिल नहीं कर सकते। आपको यह पैसा चुकाना ही होगा। सतीजा कहती हैं, आप कर्ज चुकाने में असमर्थ हैं, यह तय करने के मापदंड भी समय लेते हैं। हालांकि यह आसान फैसला नहीं है। यह प्रक्रिया भी जटिल है और इसमें काफी समय लगता है क्योंकि हम अभी पुराने कानून में अटके हैं। यह रास्ता बहुत अधिक लोगों ने नहीं चुना है, जिसके लिए कुछ हद तक सामाजिक बदनामी, कुछ हद तक पुराने नियम और कुछ हद तक वकीलों एवं अदालतों से संपर्क साधने का डर जिम्मेदार हैं। डीएसके लीगल में पार्टनर अजय शॉ ने कहा, आईबीसी एक संयोजित ढांचा है, जिसमें व्यक्तियों के लिए कर्ज न चुका पाने की स्थिति से निपटने के लिए पारदर्शी एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया है। इससे विकास के अडंगे दूर होंगे।

अयोध्या से राष्ट्र को जगाने वाले अमर नायक

अयोध्या 27 जुलाई (प्रेस सूचना केन्द्र)। आगामी 5 अगस्त को श्रीराम जन्म भूमि का पूजन होने जा रहा है। इस दिन को देखने के लिए अनगिनत संत-महात्माओं ने संघर्ष किया और मंदिर निर्माण की लड़ाई लड़ी. जिन लोगों के संघर्ष के कारण यह शुभ अवसर आया, उनमें से कुछ लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। आज जो शुभ अवसर आया है उसके पीछे सदियों का संघर्ष और लोगों की तपस्या है

परमहंस राम चन्द्र दास जी महाराज

परमहंस रामचन्द्र दास जी महाराज ने श्रीराम जन्मभूमि में पूजा-अर्चना के लिए 1950 में जिला न्यायालय में मुकदमा दायर किया। जिला अदालत ने पूजा पाठ करने की अनुमति दे दी। मुस्लिम पक्षकारों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील की। उच्च न्यायालय ने जिला आदालत के फैसले को उचित ठहराया।

दिगम्बर अखाड़ा, अयोध्या में बैठक हुई जिसमें श्रीराम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का गठन हुआ। समिति की बैठक में तय किया गया कि श्रीराम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए जन-जागरण किया जाएगा। परमहंस जी ने वर्ष 1985 के अक्टूबर माह में

महंत दिग्विजय नाथ

गोरक्षपीठ के ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ ने वर्ष, 1934 से वर्ष, 1949 तक लड़ाई लड़ी। वर्ष 1949 में विवादित जगह में जब रामलला प्रकट हुए, उसके बाद वहां पूजा-अर्चना शुरू हो गई। महंत दिग्विजय नाथ के ब्रह्मलीन होने के बाद महंत अवैद्यनाथ ने राम मंदिर आंदोलन का दायित्व संभाला और फिर राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का गठन किया। इसकी पहली यात्रा महंत अवैद्यनाथ के नेतृत्व में बिहार के सीतामढ़ी से अयोध्या तक निकाली गई।

गोपाल सिंह विशारद

जब विवाद शुरू हुआ तब गोपाल सिंह विशारद आये। यही वह व्यक्ति थे, जिन्होंने पहला मुकदमा दायर किया। एक श्रद्धालु के तौर पर गोपाल सिंह विशारद ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी कि उनके दर्शनङ्कपूजन में कोई व्यवधान न उत्पन्न किया जाए। कोर्ट ने इस पर स्थगन आदेश पारित कर दिया। विवाद की स्थिति उत्पन्न होते देख अयोध्या जनपद (उस समय का फैजाबाद) के सिटी मजिस्ट्रेट ने नगर पालिका के चेयरमैन बाबू प्रिया दत्त राम को मंदिर का रिसीवर नियुक्त कर दिया और 5 जनवरी, 1950 को इनर कोर्ट यार्ड जिसमें तीनों ढांचे जो वर्ष 1992 में ढहा दिए गए और उसके सामने की जमीन रिसीवर की देख-रेख में दे दी गई।

अशोक सिंघल

श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन के माध्यम से राष्ट्र की सुप्त पड़ी विराट चेतना एवं सोए हुए हिंदू पौरुष को जगाने का काम श्रद्धेय श्री अशोक सिंहल ने किया। संघ की कार्ययोजना से अशोक सिंघल जी 1983 में विश्व हिन्दू परिषद में भेजे गए और 1984 में विहिप के सयुंक्त महामंत्री बनाए गए. उसी वर्ष अशोक सिंघल जी ने राम जन्म भूमि के मुद्दे को उठाया। उन्होंने सन, 198 3 में दिल्ली के विज्ञान परिषद में प्रेस कांफ्रेंस करके पहली बार विहिप के बैनर से यह मांग की कि काशी, मथुरा और अयोध्या को मुक्त कराया जाएगा। सन, 1984 में राम जन्म भूमि के लिए पहली एकात्मता यात्रा निकाली गई। इसके बाद अशोक जी ने राष्ट्र के जागरण के लिए गो माता, गंगा माता और भारत माता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कई प्रदेशों से रथ यात्राएं निकाली। यह सभी रथ यात्राएं दिल्ली में आकर एकत्र हुईं।

इस बीच वर्ष, 1986 में सिविल कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर का ताला खोला गया। वर्ष, 1989 में प्रयागराज के कुम्भ में देवरहा बाबा एवं रामचंद्र परमहंसदास जी की उपस्थिति में यह तय हुआ कि गांवङ्कगांव में शिला पूजन कराया जाएगा। सबसे पहला शिला पूजन बद्रीनाथ में हुआ। पूरे भारत में पौने तीन लाख गावों से पूजन करने के बाद शिलायें मंगाई गईं। इन शिलाओं को मंदिर निर्माण में लगाया जाने का संकल्प लिया गया था। 9 नवम्बर, 1989 को विहिप ने अयोध्या में शिलान्यास किया। 29 मई, 1990 को प्रबोधिनी एकादशी को कारसेवा करने का फैसला लिया गया। अयोध्या में भारी संख्या में कारसेवक पहुंचे। इस मौके पर अशोक सिंघल जी भी अयोध्या पहुंच गए और सबको चौंका दिया। पुलिस ने अयोध्या में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अंतत: ढांचा ढहाया गया। उसके बाद से आखिरी सांस तक उनकी यही इच्छा थी कि जन्म भूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। उनका संकल्प अब यकीनन पूरा हो रहा है।

ठाकुर गुरुदत्त सिंह

अयोध्या स्थित कार्यशाला में इन दिनों हलचल तेज है। पत्थर तेजी से तराशे जा रहे हैं। कार्यशाला में काफी बड़े आकार की दो तीन तस्वीरें लगी हुई हैं। इसमें से एक तस्वीर है–ठाकुर गुरदत्त सिंह की। यह जानना काफी दिलचस्प है कि कौन थे ठाकुर गुरुदत्त सिंह? 22/23 दिसंबर, 1949 को जब भगवान राम लला प्रकट हुए थे, उस समय ठाकुर गुरुदत्त सिंह फैजाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट थे। हिन्दू विरोधी सरकार ने तत्काल मूर्ति हटवाने का आदेश दिया था मगर उन्होंने इस आदेश को मानने से इन्कार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

जनङ्कजागरण अभियान के लिए अयोध्या से 6 राम-जानकी रथों का पूजन कर विभिन्न क्षेत्रों में भेजे। परमहंस जी ने अयोध्या में घोषणा कर दी थी, अगर 8 मार्च, 1989 तक श्रीराम जन्मभूमि का ताला नहीं खुला तो मैं आत्मदाह करूंगा। इसी बीच 1 फ़रवरी, 1989 को श्री राम मंदिर का ताला खोल दिया गया।

वर्ष, 2002 के जनवरी माह में परमहंस रामचन्द्र दास जी ने अयोध्या से दिल्ली तक की चेतावनी सन्त यात्रा निकाली। सन्तों का नेतृत्व करते हुए 27 जनवरी, 2002 को प्रधानमंत्री से मुलाकात की। परमहंस जी ने अंतिम क्षण तक यह प्रयास किया कि राम जन्म भूमि विवाद का कोई हल निकल आये मगर ऐसा हो नहीं सका।

22/23 दिसंबर की रात सन 1949 को भगवान का प्राकट्य हुआ। उसके बाद से विवाद शुरू हुआ। मूर्ति प्रकट होने को लेकर

कोठारी बन्धु

कोलकाता निवासी राम कोठारी और शरद कोठारी दोनों भाइयों ने अयोध्या में ढांचे पर चढ़कर झंडा फहराया था। ढांचे की सुरक्षा के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने गोली चलाने का आदेश दिया था। 2 नवंबर, 1990 को अयोध्या में पुलिस की गोली से कोठारी बंधुओं की मृत्यु हो गई थी। अयोध्या में गोली चलने से ठीक पहले वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को बिहार के समस्तीपुर में रोक दिया गया था। उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। उस समय जो फोटो अखबारों में प्रकाशित हुई थीं, उसमें राम कोठारी, ढांचे के ऊपर हाथ में भगवा झंडा थामे खड़े दिख रहे हैं और शरद कोठारी उनके बगल में हैं।

स्वत्वाधिकारी ,मुद्रक,प्रकाशक आलोक सिंघई ने सम्यक प्रिंटर्स (रुचि प्रिंटर्स) से छापा और ऊपरी भूतल-7 अलकनंदा काम्पलेक्स जोन-1,एमपी नगर भोपाल से प्रकाशित किया।
संपादक - आलोक सिंघई फो.2555007,मोबा.-9425376322 न्याय क्षेत्र भोपाल. *aloksinghai67@gmail.com* सलाहकार संपादक:विपिन शर्मा,स्थानीय संपादक:संजय जैन।